

Vol 3 Issue 4 Oct 2013

Impact Factor : 1.2018 (GISI)

ISSN No :2231-5063

Monthly Multidisciplinary
Research Journal

*Golden Research
Thoughts*

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

IMPACT FACTOR : 0.2105

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595

ISSN No.2230-7850

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho Federal University of Rondonia, Brazil	Mohammad Hailat Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken, Aiken SC 29801	Hasan Baktir English Language and Literature Department, Kayseri
Kamani Perera Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka	Abdullah Sabbagh Engineering Studies, Sydney	Ghayoor Abbas Chotana Department of Chemistry, Lahore University of Management Sciences [PK]
Janaki Sinnasamy Librarian, University of Malaya [Malaysia]	Catalina Neculai University of Coventry, UK	Anna Maria Constantinovici AL. I. Cuza University, Romania
Romona Mihaila Spiru Haret University, Romania	Ecaterina Patrascu Spiru Haret University, Bucharest	Horia Patrascu Spiru Haret University, Bucharest, Romania
Delia Serbescu Spiru Haret University, Bucharest, Romania	Loredana Bosca Spiru Haret University, Romania	Ilie Pinteau, Spiru Haret University, Romania
Anurag Misra DBS College, Kanpur	Fabricio Moraes de Almeida Federal University of Rondonia, Brazil	Xiaohua Yang PhD, USA
Titus Pop	George - Calin SERITAN Postdoctoral Researcher	Nawab Ali Khan College of Business Administration

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India	Iresh Swami Ex - VC. Solapur University, Solapur	Rajendra Shendge Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur
R. R. Patil Head Geology Department Solapur University, Solapur	N.S. Dhaygude Ex. Prin. Dayanand College, Solapur	R. R. Yaliker Director Managment Institute, Solapur
Rama Bhosale Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel	Narendra Kadu Jt. Director Higher Education, Pune	Umesh Rajderkar Head Humanities & Social Science YCMOU, Nashik
Salve R. N. Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur	K. M. Bhandarkar Praful Patel College of Education, Gondia	S. R. Pandya Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai
Govind P. Shinde Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai	Sonal Singh Vikram University, Ujjain	Alka Darshan Shrivastava Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar
Chakane Sanjay Dnyaneshwar Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune	G. P. Patankar S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka	Rahul Shriram Sudke Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore
Awadhesh Kumar Shirotriya Secretary, Play India Play (Trust),Meerut	Maj. S. Bakhtiar Choudhary Director,Hyderabad AP India.	S.KANNAN Ph.D , Annamalai University,TN
	S.Parvathi Devi Ph.D.-University of Allahabad	Satish Kumar Kalhotra
	Sonal Singh	

**Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net**



सरकार द्वारा कृषि के लिये दी जाने वाली सूचनाओं के बारे में किसानों की संतुष्टि का अध्ययन



विक्रम कौशिक , परमवीर सिंह

असोसिएट प्रोफेसर, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं तकनीक विश्वविद्यालय, हिसार ,
असीसटेंट प्रोफेसर, झारखण्ड केन्द्रिय विश्वविद्यालय, ब्राम्बे, रांची

सारांश : सूचना का प्रवाह समृद्धि को सुनिश्चित करता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में सूचनाओं के प्रवाह को बढ़ाकर ग्रामीणों में जागरूकता स्तर को बढ़ाया जा सकता है जिसका लाभ उन्हें उन्नत जीवन स्तर और आर्थिक समृद्धि के रूप में मिलेगा। किसानों को सूचना प्रसारित करते समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उनकी प्रत्येक जरूरत सूचना से पूरी होनी चाहिए। किसानों को कृषि के लिये बहुत सारी सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। किसान को फसल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं आवश्यक होती हैं, जैसे उसे कौन सी फसल बोनी चाहिए, कैसे बोई जानी चाहिए, उसका भण्डारण कैसे करना चाहिए, फसल को कब और कहाँ सही दाम पर बेचा जा सकता है। यानी किसान को फसल के प्रकार से लेकर उसे बेचने तक बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जिनके लिये उसे सरकारी या नीजि सूचना तंत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। जो किसान बाजार के रूझानों और सम्भावनाओं को सही समय पर समझ लेता है वह कृषि में ज्यादा मुनाफा कमा लेता है, बाजार के रूझानों को समझने के लिये सही समय पर सही सूचना, सही माध्यम के द्वारा किसान तक पहुंचना आवश्यक है। भारतीय किसान आयोग का भी मानना है कि किसानों के पास सही सूचनाओं का अभाव है जिस कारण उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिये सरकार को बेहतर सूचना ढांचा विकसित करने पर जोर देना चाहिए ताकि किसानों को समय रहते सूचनाएं प्रदान की जा सकें।

प्रस्तावना :

भारत में ज्यादातर किसान सीमांत हैं जिस कारण वे ज्यादा जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिये सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं का उन तक पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में सूचनाओं का किसानों तक ना पहुंच पाना किसानों की समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या है। उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करने के लिये कई प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता किसानों को पड़ती है। फसल की बिजाई, भण्डारण व विक्रय के अलावा बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं, जो किसानों को कृषि के लिये बेहद आवश्यक हैं। जैसे—

- 1 सरकार के कृषि से जुड़े नीतिगत फैसलों की सूचना।
- 2 ज्यादा पैदावार के लिये रसायनों के सही प्रयोग की सूचनाएं।
- 3 फसल को लगने वाली बिमारियां और उनके बचाव के उपायों के बारे में सूचना।
- 4 सिंचाई से जुड़ी सूचनाएं, जैसे— सिंचाई के लिये उपलब्ध माध्यमों के प्रयोग की सूचना, जल संरक्षण और नई सिंचाई तकनीकों के बारे में।
- 5 उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की प्रजाति, उनके प्रयोग की उचित मात्रा आदि से जुड़ी सूचनाएं।
- 6 फसल की गुणवत्ता व बिना नुकसान के उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये कदम दर कदम सूचना।
- 7 मृदा संवर्धन के लिये फसल चक्र से जुड़ी सलाह।
- 8 फल व सब्जियां जैसी ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल के बारे में सलाह
- 9 जल्दी खराब होने वाली फसलों के लिये उपलब्ध भण्डारण सुविधाओं से जुड़ी सूचनाएं।

किसानों के पास सही जानकारी नहीं होने के कारण सिंचाई के लिये उपलब्ध पानी का सही प्रयोग नहीं कर पाते जिसके कारण एक तिहाई भारत में सुखे जैसे हालात रहते हैं। किसानों के पास फसल की सिंचाई के लिये उपलब्ध नई पद्धतियों की जानकारी का अभाव रहता है जिस कारण वे उपलब्ध पानी का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा किसानों को फसल के लिये सही बीजों की प्रजाति और अनेकों पौधों के बारे में जानकारी नहीं रहती है। देश में कई पौधे और जड़ी-बुटियां ऐसी हैं जिनका उत्पादन करके किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी के साथ वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के लिये सही बीजों के ज्ञान ना होने के कारण किसान उन फसलों का लाभ नहीं उठा पाते। इसके अलावा किसान इन सबकी उपलब्धता के सही समय व स्थान के बारे में जागरूक नहीं होते हैं, जिस कारण वे इन सम्भावनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

फसल उत्पादन के लिये सही तकनीक की जानकारी के अभाव में भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि कई ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत में

ग्रामीण क्षेत्र में तकनीक को पहुंचाने के लिये कार्यरत हैं, लेकिन अभी भी किसानों के पास सही तकनीक के प्रयोग सम्बन्धी सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। इसके अलावा किसानों के पास उपलब्ध तकनीकों के प्रयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में नगण्य है, जिस कारण किसान तकनीक का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं जिसका नुकसान उन्हें आर्थिक रूप में चुकाना पड़ता है।

किसान को फसल उत्पादन के लिये आवश्यक सभी सूचनाओं के सही प्रसार के लिये सरकार शुरु से ही कार्यरत है। ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसी सरकारी इकाईयां हैं जो किसानों को हर सम्भव सूचना उपलब्ध करवाने में लगी हैं। फसल बोआई से लेकर उसके विक्रय तक किसानों को कई स्तर पर सूचनाओं की आवश्यकता रहती है, जिसके उपलब्ध ना होने के परिणाम फसल उत्पादन में गिरावट, उपलब्ध संसाधनों का गलत प्रयोग और आर्थिक हानि के रूप में सामने आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सूचना के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा कई संस्थानों की स्थापना की है, जो कि किसानों को सूचना उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनके प्रशिक्षण और सलाह देने का भी कार्य कर रहे हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है कि सरकार द्वारा प्रसारित सूचना की विश्वसनीयता, सही समय और बारम्बारता के बारे में किसानों का क्या मत है?

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये आयोजित किया गया है—

- 1 कृषि के लिये सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सूचनाओं की विश्वसनीयता के बारे में किसानों की राय जानना।
- 2 कृषि के लिये सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सूचनाओं के सही समय के बारे में किसानों की राय जानना।
- 3 कृषि के लिये सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सूचनाओं की बारम्बारता के बारे में किसानों की राय को जानना।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध पत्र के लिये आंकड़े एकत्रित करने के लिये हरियाणा राज्य के सिरसा जिले पर अध्ययन किया गया है। सिरसा जिले के पांच गांवों को नमूने के तौर पर लेकर आंकड़े एकत्रित किये गये हैं। इन गांवों का चयन जिला मुख्यालय से दूरी और दिशा के अनुसार किया गया है। प्रत्येक गांव से 100 किसानों का चयन दैव निदर्शन विधि के माध्यम से करके आंकड़े एकत्रित किये गये हैं। सिरसा जिले के औढ़ा, बड़ागुड़ा, संतनगर, गिगोरानी और फरवाई गांव का चयन करके आंकड़े एकत्रित किये गये हैं।

साहित्य की समीक्षा

अशोक नारंग ने अपनी पुस्तक "ग्रामीण भारत की समस्याएं" में लिखा है कि ग्रामीण भारत, ग्रामीण लोग व ग्रामीण संसाधन देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश देश के नीति निर्धारक व जनसंचार माध्यम ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं पर बहुत कम ध्यान देते हैं। कई राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने ग्रामीण भारत के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम व परियोजनाएं लागू की हैं लेकिन विकास की वास्तविकता अभी दूर है।

भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित कुरुक्षेत्र पत्रिका के जनवरी 2007 अंक के लेख में तथ्य दिये गए हैं कि भारत के 13 गरीब राज्यों की 15 प्रतिशत जनसंख्या को दिन में एक समय भूखा रहना पड़ता है। यानी विकास की लहर यहां लाई जानी जरूरी है। भले ही देश का सूचकांक 20000 के आंकड़े पर उछल रहा हो और समाचार पत्रों व चैनलों की सुर्खियों में हो लेकिन इस 15 प्रतिशत जनसंख्या के बारे में भी सरकार का दायित्व बनता है।

डॉ.बी.एस. दलाल जो कि एपेक्स बैंक में वित्तीय विशेषज्ञ के रूप में पिछले 37 वर्षों से कार्यरत हैं। उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि परम्परागत भारतीय कृषि को अब आधुनिकतम ई-एग्रीकल्चर की ओर बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी स्तरों पर प्रयास किया जाना बेहद जरूरी है। इसके लिए आसान नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि अनपढ़ व छोटे किसान दूसरी हरित क्रांति की ओर अग्रसर हो सकें। सूचना व प्रसारण के इस युग में आई.सी.टी. का प्रयोग बेहतर ढंग से किया जा सकता है। सूचना सम्प्रेषण तकनीकों के माध्यम से किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र की दूसरी हरित क्रांति का स्वागत आई.सी.टी. द्वारा उदार मन से किया जाना चाहिए।

'वैश्विकरण की कमीयां- विकासशील देशों में सूचना संचार तकनीक और ई-वाणिज्य का प्रयोग' शिर्षक से किये गये शोध में जे. कामसू, जे.एस. सिकपे, जे. एलजी और अरोरा जे. कामसू कहते हैं कि सूचना और संचार तकनीक गरीबी से लड़ने का एक महत्वपूर्ण औजार बन गया है। सूचना संचार तकनीक विकासशील देशों को गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा जैसे विकासत्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। जो देश सूचना संचार तकनीक की सम्भावनाओं का सही लाभ उठा रहे हैं वे आर्थिक प्रगति, मानव कल्याण व लोकतन्त्र की मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं।

दैनिक जागरण के 16 अक्टूबर 2010 के अंक में 'मोबाइल से गरीबी भी होती है दूर' में कहा गया है कि दूरियां मिटाने वाले मोबाइल फोन से गरीबी भी दूर हो सकती है। संचार के इस साधन से गुरबत का अंधेरा दूर करने और लोगों का जीवन स्तर उंचा उठाने में मदद मिलती है। इसमें सरकार की अहम भूमिका है। संचार माध्यमों का प्रसार-प्रचार करना और उन्हें जरूरतमंद लोगों तक सस्ते मूल्य पर मुहैया करवाना उसकी जिम्मेवारी है।

दैनिक जागरण के 29 दिसम्बर 2010 के अंक में अश्विनी शर्मा अपने समाचार 'अब एसएमएस से सीखें खेती से गुर' में लिखते हैं कि अब मोबाइल पर एसएमएस के जरिये किसानों को वैज्ञानिक विधि से खेती के गुर बताये जायेंगे। खास बात यह है कि किसानों को संदेश हरियाणवी भाषा में भेजा जायेगा ताकि वे सीधा संवाद स्थापित कर सकें और संदेश को भली भांति समझ सकें।

एस.सी मितल अपने शोध पत्र 'कृषि में सूचना तकनीक' में लिखते हैं कि भारतीय कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों का सही दोहन नहीं किया जा सका है। सूचना प्रौद्योगिकी ने नीति निर्माताओं के लिये निर्णय लेने के लिये नई सम्भावनाओं को जन्म दिया है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान संतोषजनक नहीं है। इस पत्र में कृषि क्षेत्र के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपयोगों के बारे में बताया गया है। इसमें उर्वरकों के विपणन में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोगों पर खास ध्यान दिया गया है।

डॉ. सुनील फोगाट अपने शोध कृषि में सूचना तकनीक की भूमिका में कहते हैं कि ज्यादा सूचना का प्रवाह कृषि पर सकारात्मक प्रभाव डालता है लेकिन सूचना की प्राप्ति व सूचना प्रसारण आज भी दूर्गम व महंगी है। सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के प्रवाह को बढ़ाती है व सूचना की लागत को कम करती है। भारतीय कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से लागू करके सामाजिक आर्थिक विकास किया जा सकता है। आज भी हमारे देश में किसान आसानी से सूचना प्राप्त करने में असमर्थ हैं जिससे वे खेत सम्बन्धि निर्णय ले पायें।

जोनी सी जोसेफ अपनी पुस्तक मास मीडिया एण्ड रूरल डेवलपमेंट में कहते हैं तिसरी दुनिया के देशों की संस्कृति ग्रामीण है तथा कृषि पर आधारित है। इन देशों का सबसे बड़ा उद्देश्य आधुनिकीकरण व कृषि विकास को प्राप्त करना है। लेकिन विकास के अन्य माध्यमों के साथ-साथ जनसंचार माध्यम कृषि विकास जैसे मुद्दों पर अपनी भूमिका सही नहीं निभा रहे हैं। भारत जैसे देश में

जहां 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और ज्यादातर ग्रामीण अनपढ़ हैं वहां जनसंचार व विकास के अन्य माध्यमों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जनसंचार सिर्फ खबर देने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि अपने आप में एक सम्पूर्ण माध्यम है जो समाज की विचारधारा में क्रांति ला सकता है।

आंकड़ा प्रस्तुतीकरण**तालिका संख्या-1****बाजार में आये नई किसम के बीज, खाद और कीटनाशकों के बारे में सूचना**

सूचना की विश्वसनीयता	किसानों की संख्या व प्रतिशत	सूचना का सही समय	किसानों की संख्या व प्रतिशत	सूचना की बारम्बारता	किसानों की संख्या व प्रतिशत
बहुत ज्यादा	0 (0)	बहुत ज्यादा	0 (0)	बहुत ज्यादा	0 (0)
ज्यादा	4 (0.8)	ज्यादा	22 (4.4)	ज्यादा	60 (12)
कम	177 (35.4)	कम	220 (44)	कम	320 (64)
बहुत कम	262 (52.4)	बहुत कम	184 (36.8)	बहुत कम	120 (24)
बिल्कुल नहीं	57 (11.4)	बिल्कुल नहीं	74 (14.8)	बिल्कुल नहीं	0 (0)

किसान को फसल बोन से पहले गुणवत्तापूर्ण नये बीजों की बाजार उपलब्धता के बारे में सूचनाओं की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा बाजार में आये नये किसम के खाद व कीटनाशकों से जुड़ी सूचनाओं की आवश्यकता भी किसानों को पडती है। इस सम्बन्ध सरकार द्वारा कई माध्यमों से सूचनाओं का प्रसार करती है। इस विषय पर किसानों से जानने पर यह सामने आया कि किसान सरकार द्वारा बाजार में आये नये बीजों, खाद व कीटनाशकों के बारे में दी जाने वाली सूचनाओं पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। लगभग 52 प्रतिशत किसान सरकार द्वारा इस विषय में दी जाने वाली सूचना पर बहुत कम विश्वासनीय मानते हैं। वहीं लगभग 11 प्रतिशत किसान इन सूचनाओं को बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं मानते, जबकि लगभग 34 प्रतिशत किसान इन सूचनाओं को कम विश्वसनीय मानते हैं। सिर्फ 1 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो इन सूचनाओं को विश्वसनीय मानते हैं।

कृषि के लिये सूचना का महत्व इस बात पर टिका रहता है कि वह किसानों तक सही समय पर पहुंचाई जाये। बाजार में आये नये बीज, खाद व कीटनाशकों के बारे में सरकार द्वारा सूचना सही समय पर पहुंचाई जाती है या नहीं इस विषय में पूछे जाने पर ज्यादातर किसानों ने प्रतिक्रिया नकारात्मक दी है। 44 प्रतिशत किसानों का कहना है कि इस विषय में दी जाने वाली सूचना कम सही समय में उन तक पहुंचती है। जबकि 36 प्रतिशत किसान मानते हैं कि इन सूचनाओं के प्रसारण का समय बहुत कम सही होता है। जबकि 14 प्रतिशत किसानों का मानना है कि इन सूचनाओं के प्रसारण का समय बिल्कुल सही नहीं होता है। सिर्फ 4 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि सरकार द्वारा इस विषय पर दी जाने वाली सूचना सही समय पर उन तक पहुंचा दी जाती है।

सूचना के सही प्रयोग और परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि उसे बार-बार किसानों तक पहुंचाया जाये। बाजार में आये नये खाद, बीज और कीटनाशकों के बारे में प्रसारित सरकारी सूचना की बारम्बारता पर आंकड़े एकत्रित करने पर यह सामने आया कि सरकार द्वारा प्रसारित सूचना की बारम्बारता ज्यादा नहीं है। 64 प्रतिशत किसान यह मानते हैं कि इन सूचनाओं की बारम्बारता कम रहती है। जबकि 24 प्रतिशत किसानों का कहना है कि इन सूचनाओं की बारम्बारता बहुत कम रहती है। वहीं 12 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनका मानना है कि सरकार द्वारा इस विषय पर दी जाने वाली सूचना की बारम्बारता ज्यादा रहती है।

तालिका संख्या-2**कृषि के नये प्रकार के उपकरणों के बारे में सूचना**

सूचना की विश्वसनीयता	किसानों की संख्या व प्रतिशत	सूचना का सही समय	किसानों की संख्या व प्रतिशत	सूचना की बारम्बारता	किसानों की संख्या व प्रतिशत
बहुत ज्यादा	0 (0)	बहुत ज्यादा	0 (0)	बहुत ज्यादा	0 (0)
ज्यादा	0 (0)	ज्यादा	9 (1.8)	ज्यादा	72 (14.4)
कम	115 (23)	कम	253 (50.6)	कम	278 (56.6)
बहुत कम	244 (48.8)	बहुत कम	203 (40.6)	बहुत कम	149 (29.8)
बिल्कुल नहीं	141 (28.2)	बिल्कुल नहीं	35 (7)	बिल्कुल नहीं	1 (0.2)

कृषि उत्पादन को बढ़ाने और किसानों के श्रम को कम करने के लिये समय-समय पर नये उपकरण बाजार में आते रहते हैं। सरकार द्वारा इस बारे में सूचनाएं किसानों तक पहुंचाई जाती हैं। प्रस्तुत तालिका में इस विषय पर आंकड़े पेश किये गये हैं। तालिका के आंकड़ों से स्पष्ट है कि ज्यादातर किसान सरकार द्वारा इस विषय पर दी जाने वाली सूचनाओं को विश्वसनीय नहीं मानते हैं।

लगभग 48 प्रतिशत किसानों इन सूचनाओं को बहुत कम विश्वसनीय मानते हैं, जबकि 28 प्रतिशत किसान इन सूचनाओं को बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं मानते हैं। वहीं 23 प्रतिशत किसानों का मानना है कि सरकार द्वारा नये उपकरणों के बारे में दी जाने वाली विश्वसनीयता कम होती है।

बाजार में आये नये उपकरणों के बारे में प्रसारित होने वाली सरकारी सूचनाओं के सही समय के बारे में आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ कि लगभग 50 प्रतिशत किसान ऐसा मानते हैं कि इस विषय पर दी जाने वाली सरकारी सूचना का समय कम सही होता है। जबकि लगभग 41 प्रतिशत किसानों का मानना है नये उपकरणों के बारे में सरकारी सूचना का समय बहुत कम सही होता है। 7 प्रतिशत किसान ऐसा मानते हैं कि सरकार द्वारा प्रसारित सूचनाओं का समय बिल्कुल सही नहीं होता है। सिर्फ 2 प्रतिशत किसान ऐसा मानते हैं कि सरकार द्वारा नये उपकरणों के बारे में दी जाने वाली सूचनाओं का समय सही होता है।

इस विषय पर सूचनाओं की बारम्बारता के बारे में जानने पर यह सामने आया कि 55 प्रतिशत किसानों का मानना है कि सरकार की सूचना की बारम्बारता कम रहती है, वहीं 30 प्रतिशत किसानों का मानना है कि इस विषय पर सरकार की सूचना की बारम्बारता बहुत कम रहती है। शोध के दौरान 7 प्रतिशत ऐसे किसान भी सामने आये जिनका मानना है कि सरकारी सूचनाओं की बारम्बारता सही होती है।

तालिका संख्या-3 कृषि की नई पद्धति के बारे में सूचना

सूचना की विश्वसनीयता	किसानों की संख्या व प्रतिशत	सूचना का सही समय	किसानों की संख्या व प्रतिशत	सूचना की बारम्बारता	किसानों की संख्या व प्रतिशत
बहुत ज्यादा	0 (0)	बहुत ज्यादा	0 (0)	बहुत ज्यादा	0 (0)
ज्यादा	7 (1.4)	ज्यादा	27 (5.4)	ज्यादा	0 (0)
कम	173 (34.6)	कम	182 (36.4)	कम	82 (16.4)
बहुत कम	258 (51.6)	बहुत कम	216 (43.2)	बहुत कम	238 (47.6)
बिल्कुल नहीं	62 (12.4)	बिल्कुल नहीं	75 (15)	बिल्कुल नहीं	180 (36)

कृषि की पद्धतियों में कई बदलाव होते रहते हैं। इन नई पद्धतियों के बारे में जागरूकता को सुनिश्चित किया जाये तो किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। कृषि की नई पद्धतियों के बारे में सरकार द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं के बारे में किसानों का मानना है कि उनकी विश्वसनीयता काफी कम होती है। 51 प्रतिशत किसान यह मानते हैं कि कृषि की नई पद्धतियों के बारे में सरकार द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं की विश्वसनीयता बहुत कम होती है। जबकि 34 प्रतिशत किसान इन सूचनाओं को कम विश्वसनीय मानते हैं। इसके अलावा 12 प्रतिशत किसान यह मानते हैं कि इन सूचनाओं की विश्वसनीयता बिल्कुल भी नहीं होती है। सिर्फ 1 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनका मानना है कि सरकार द्वारा कृषि की नई पद्धतियों के बारे में दी जाने वाली सूचनाओं की विश्वसनीयता ज्यादा होती है।

कृषि की नई पद्धतियों के बारे में सरकार द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं का समय बहुत कम सही होता है, ऐसा मानने वाले किसानों का प्रतिशत लगभग 43 है, जबकि 36 प्रतिशत किसानों का मानना है कि ऐसी सूचनाओं के उन तक पहुंचाए जाने का समय कम सही होता है। 15 प्रतिशत किसान यह मानते हैं कि कृषि की नई सूचनाओं से सम्बन्धित सरकारी सूचनाओं का समय बिल्कुल सही नहीं होता। सिर्फ 5 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि ऐसी सूचनाओं का समय सही होता है।

कृषि की नई पद्धतियों के बारे में सरकारी सूचनाओं के बारे में किसानों की राय सकारात्मक नहीं है। 43 प्रतिशत किसानों की राय में ऐसी सूचनाओं की बारम्बारता बहुत कम है, जबकि 36 प्रतिशत किसान ऐसा मानते हैं कि कृषि की नई पद्धतियों से जुड़ी सूचनाओं की बारम्बारता बिल्कुल भी नहीं होती। 16 प्रतिशत किसानों का मानना है कि ऐसी सूचनाओं की बारम्बारता कम होती है।

तालिका संख्या-4 सरकारी मूल्य पर बीज, खाद व कीटनाशक की उपलब्धता की सूचना

सूचना की विश्वसनीयता	किसानों की संख्या व प्रतिशत	सूचना का सही समय	किसानों की संख्या व प्रतिशत	सूचना की बारम्बारता	किसानों की संख्या व प्रतिशत
बहुत ज्यादा	0 (0)	बहुत ज्यादा	0 (0)	बहुत ज्यादा	45 (9)
ज्यादा	137 (27.4)	ज्यादा	133 (26.6)	ज्यादा	147 (29.4)
कम	261 (52.2)	कम	237 (47.4)	कम	223 (44.6)
बहुत कम	102 (20.4)	बहुत कम	130 (26)	बहुत कम	79 (15.8)
बिल्कुल नहीं	0 (0)	बिल्कुल नहीं	0 (0)	बिल्कुल नहीं	6 (1.2)

अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सरकार कृषि के लिये रियायती मूल्य पर बीज, खाद और कीटनाशक की उपलब्धता करवाती है। लेकिन उनकी उपलब्धता की सूचना के अभाव के कारण किसान उनका लाभ नहीं उठा पाते। किसानों को सरकारी मूल्य पर उपलब्ध बीज, खाद और कीटनाशक की उपलब्धता के बारे में सूचनाओं की विश्वसनीयता के बारे में किसानों की राय मिली जुली है। 52 प्रतिशत किसानों का मानना है कि इस विषय पर दी जाने वाली सूचनाओं कम विश्वसनीय होती है, जबकि 27 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनका मानना है कि इन सूचनाओं की विश्वसनीयता ज्यादा होती है। 20 प्रतिशत किसान मानते हैं कि सरकारी मूल्य पर बीज, खाद और कीटनाशकों की उपलब्धता के बारे में सूचनाएं बहुत कम विश्वसनीय होती हैं।

कृषि के लिये सरकारी मूल्य पर उपलब्ध बीज, खाद और कीटनाशकों से सम्बन्धित सूचनाओं के प्रसारण के सही समय के बारे में किसानों में से 47 प्रतिशत किसान मानते हैं कि ऐसी सूचनाओं के प्रसारण का समय कम सही होता है। जबकि लगभग 26 प्रतिशत किसान मानते हैं कि किसानों को इस विषय पर दी जाने वाली सूचनाओं का समय ज्यादा सही होता है। 26 प्रतिशत किसानों का मानना है कि इन सूचनाओं का समय बहुत कम सही होता है।

बारम्बारता के बारे में 44 प्रतिशत किसानों का मत है कि इन सूचनाओं की आवृत्ति कम होती है। जबकि 29 प्रतिशत किसानों का मानना है कि इन विषय पर दी जाने वाली सूचनाओं की बारम्बारता ज्यादा होती है। 15 प्रतिशत किसानों की राय में ऐसी सूचनाओं की बारम्बारता बहुत कम होती है, वहीं 9 प्रतिशत किसान यह मानते हैं कि ऐसी सूचनाओं की बारम्बारता बहुत ज्यादा होती है। लगभग 1 प्रतिशत किसान ऐसा मानते हैं कि किसानों को सरकार द्वारा सरकारी मूल्य पर उपलब्ध बीज, खाद और कीटनाशकों की उपलब्धता के बारे में दी जाने वाली सूचनाओं की बारम्बारता बिल्कुल भी नहीं होती है।

तालिका संख्या-5 कृषि के लिये आवश्यक उपकरणों व उत्पादों पर दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में सूचना

सूचना की विश्वसनीयता	किसानों की संख्या व प्रतिशत	सूचना का सही समय	किसानों की संख्या व प्रतिशत	सूचना की बारम्बारता	किसानों की संख्या व प्रतिशत
बहुत ज्यादा	28 (5.6)	बहुत ज्यादा	27 (5.4)	बहुत ज्यादा	72 (14.2)
ज्यादा	216 (43.2)	ज्यादा	188 (37.6)	ज्यादा	132 (26.4)
कम	231 (46.2)	कम	202 (40.4)	कम	293 (58.6)
बहुत कम	25 (5)	बहुत कम	83 (16.6)	बहुत कम	3 (0.6)
बिल्कुल नहीं	0 (0)	बिल्कुल नहीं	0 (0)	बिल्कुल नहीं	0 (0)

सरकार द्वारा किसानों को कृषि उपकरणों और उत्पादों पर सब्सिडी दी जाती है। इस बारे में सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सूचनाओं के बारे में प्रस्तुत आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि इस बारे में किसानों की राय एक नहीं है। 46 प्रतिशत किसानों का कहना है कि इस विषय पर दी जाने वाली सूचनाओं की विश्वसनीयता कम होती है, वहीं 43 प्रतिशत किसान यह मानते हैं ऐसी सूचनाओं की विश्वसनीयता ज्यादा होती है, साथ ही लगभग 5 प्रतिशत किसान ऐसा मानते हैं कि ऐसी सूचनाओं की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा होती है। 5 प्रतिशत किसान ही ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि इन सूचनाओं की विश्वसनीयता बहुत कम होती है।

40 प्रतिशत किसान यह मानते हैं कि कृषि के लिये अनुदान सम्बन्धी सूचनाओं का समय कम सही होता है, वहीं 37 प्रतिशत किसानों की राय में ऐसी सूचनाओं का समय ज्यादा सही रहता है। 16 प्रतिशत किसानों का कहना है कि कृषि अनुदान से जुड़ी सूचनाओं का सही समय बहुत कम सही होता है, जबकि लगभग 5 प्रतिशत किसानों का मानना है कि इन सूचनाओं का उन तक पहुंचाने का समय बहुत ज्यादा सही रहता है।

सरकारी अनुदान सम्बन्धी सूचनाओं की बारम्बारता के बारे में 58 प्रतिशत किसान यह मानते हैं कि ऐसी सूचनाओं की आवृत्ति कम रहती है। जबकि लगभग 26 प्रतिशत किसान यह मानते हैं कि ऐसी सूचनाओं की बारम्बारता ज्यादा होती है। 15 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जो यह मानते हैं कि अनुदान से सम्बन्धित सूचनाओं की बारम्बारता बहुत ज्यादा रहती है।

तालिका संख्या-6
फसल के लिये आवश्यक श्रृण से सम्बन्धित सूचना

सूचना की विश्वसनीयता	किसानों की संख्या व प्रतिशत	सूचना का सही समय	किसानों की संख्या व प्रतिशत	सूचना की बारम्बारता	किसानों की संख्या व प्रतिशत
बहुत ज्यादा	54 (10.8)	बहुत ज्यादा	3 (0.6)	बहुत ज्यादा	0 (0)
ज्यादा	259 (51.8)	ज्यादा	147 (29.4)	ज्यादा	183 (36.6)
कम	172 (34.4)	कम	250 (50)	कम	237 (47.4)
बहुत कम	15 (3)	बहुत कम	100 (20)	बहुत कम	80 (16)
बिल्कुल नहीं	0 (0)	बिल्कुल नहीं	0 (0)	बिल्कुल नहीं	0 (0)

सरकार की कृषि नीति के उद्देश्यों में यह शामिल है कि किसानों को समय रहते कृषि के लिये आवश्यक श्रृण उपलब्ध करवाया जाये ताकि किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाया जा सके। फसल के लिये आवश्यक श्रृण से सम्बन्धित सूचना के बारे में सरकार द्वारा कई माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। सरकार द्वारा प्रसारित इन सूचनाओं के बारे में दी जाने वाली सूचनाओं की विश्वसनीयता के बारे में 52 प्रतिशत किसान ऐसे जो यह मानते हैं कि इन सूचनाओं की विश्वसनीयता ज्यादा होती है, जबकि 34 प्रतिशत किसानों की राय में इन सूचनाओं की विश्वसनीयता कम होती है। वहीं 11 प्रतिशत किसानों का कहना है कि श्रृण से सम्बन्धित सूचनाओं की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा होती है। 3 प्रतिशत किसान इन सूचनाओं को बहुत कम विश्वसनीय मानते हैं।

श्रृण से सम्बन्धित सूचनाओं के प्रसार के समय पर आंकड़े एकत्रित करने पर यह बात सामने आई कि 50 प्रतिशत किसान यह मानते हैं कि इस विषय पर दी जाने वाली सूचनाओं का समय कम सही होता है जबकि 29 प्रतिशत किसानों का मानना है कि इस प्रकार की सूचनाओं के प्रसार का समय ज्यादा सही होता है। 20 प्रतिशत किसानों का मत है कि श्रृण से सम्बन्धित सूचनाओं के प्रसार का समय बहुत कम सही रहता है वहीं सिर्फ एक प्रतिशत किसान यह मानते हैं कि इन सूचनाओं के प्रसार की सटीकता बहुत ज्यादा होती है।

बारम्बारता के बारे में आंकड़ों से स्पष्ट है कि 47 प्रतिशत किसानों के अनुसार इन सूचनाओं की बारम्बारता बहुत कम रहती है जबकि 36 प्रतिशत किसान मानते हैं कि इन सूचनाओं की बारम्बारता ज्यादा रहती है। 16 प्रतिशत किसान ऐसे भी हैं जिनका मत है कि श्रृण से जुड़ी सूचनाओं की बारम्बारता बहुत कम रहती है।

तालिका संख्या-7
बीजी गई फसल की देखरेख के बारे में सूचना

सूचना की विश्वसनीयता	किसानों की संख्या व प्रतिशत	सूचना का सही समय	किसानों की संख्या व प्रतिशत	सूचना की बारम्बारता	किसानों की संख्या व प्रतिशत
बहुत ज्यादा	0 (0)	बहुत ज्यादा	0 (0)	बहुत ज्यादा	0 (0)
ज्यादा	6 (1.2)	ज्यादा	0 (0)	ज्यादा	0 (0)
कम	183 (36.6)	कम	115 (23)	कम	67 (13.4)
बहुत कम	268 (53.6)	बहुत कम	244 (48.8)	बहुत कम	262 (52.4)
बिल्कुल नहीं	43 (8.6)	बिल्कुल नहीं	141 (28.2)	बिल्कुल नहीं	171 (34.2)

किसानों को बीजी गई फसल की देखरेख से जुड़ी सूचनाओं की आवश्यकता रहती है, जिसके लिये सरकार समय-समय पर सूचनाओं का प्रसारण करती है। इन सूचनाओं की विश्वसनीयता के बारे में किसानों का कहना है कि यह विश्वसनीयता के मापदण्ड पर खरा नहीं उतरती है। 53 प्रतिशत किसान यह मानते हैं उन्हे बीजी गई फसल की देखरेख के बारे में मिलने वाली सरकारी सूचना बहुत कम विश्वसनीय होती है। वहीं 36 प्रतिशत किसानों के मतानुसार इस प्रकार की सूचनाएं कम विश्वसनीय होती हैं। जबकि 9 प्रतिशत किसान यह मानते हैं कि फसल देखरेख से जुड़ी सूचनाएं बिल्कुल विश्वसनीय नहीं होती है। सिर्फ एक प्रतिशत किसानों का मानना है कि इस प्रकार की सूचनाओं की विश्वसनीयता ज्यादा होती है।

किसानों द्वारा बीजी गई फसल की देखरेख से जुड़ी सूचनाओं के प्रसार समय की सटीकता के बारे में पुछने पर 48 प्रतिशत किसानों ने यह माना कि इस प्रकार की सूचनाएं सही समय पर उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। इनके प्रसार का समय बहुत कम सही होता है। वहीं 28 प्रतिशत किसान कहते हैं फसल देखरेख से जुड़ी सूचनाएं बिल्कुल भी सही समय पर उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। 23 प्रतिशत किसान यह मत रखते हैं कि बीजी गई फसल की देखरेख से सम्बन्धित सूचनाओं का ज्यादा सही रहता है।

बारम्बारता के पैमाने पर इस प्रकार की सूचनाएं ज्यादा सही नहीं रहती हैं। 52 प्रतिशत किसानों का मानना है बीजी गई फसल की देखरेख के बारे में सरकार द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं बहुत कम बार किसानों तक पहुंच पाती हैं। 34 प्रतिशत किसानों का मानना है कि ऐसी सूचनाओं की आवृत्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। जबकि सिर्फ 13 प्रतिशत किसानों का मानना है कि ऐसी सूचनाओं की

बारम्बारता ज्यादा होती है।

तालिका संख्या-8
फसल के समर्थन मूल्य के निर्धारण के बारे में सूचना

सूचना की विश्वसनीयता	किसानों की संख्या व प्रतिशत	सूचना का सही समय	किसानों की संख्या व प्रतिशत	सूचना की बारम्बारता	किसानों की संख्या व प्रतिशत
बहुत ज्यादा	153 (30.6)	बहुत ज्यादा	84 (16.8)	बहुत ज्यादा	84 (16.8)
ज्यादा	255 (51)	ज्यादा	229 (45.8)	ज्यादा	229 (45.8)
कम	87 (17.4)	कम	180 (36)	कम	180 (36)
बहुत कम	5 (1)	बहुत कम	4 (0.8)	बहुत कम	4 (0.8)
बिल्कुल नहीं	0 (0)	बिल्कुल नहीं	3 (0.6)	बिल्कुल नहीं	3 (0.6)

सरकार कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। लेकिन सरकारी समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर अक्सर पाया जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के बारे में सरकार द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं को किसान विश्वसनीय मानते हैं। उपरोक्त तालिका के आंकड़ों से स्पष्ट है कि 51 प्रतिशत किसान समर्थन मूल्य से जुड़ी सरकारी सूचनाओं को ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं, वहीं 30 प्रतिशत किसान इन सूचनाओं को बहुत ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं। सिर्फ 17 प्रतिशत किसानों का मानना है कि सरकार की फसल समर्थन मूल्य से जुड़ी सूचनाओं की विश्वसनीयता कम होती है। वहीं 1 प्रतिशत किसान इन सूचनाओं को बहुत कम विश्वसनीय मानते हैं।

फसल समर्थन मूल्य से सम्बन्धित सूचनाओं के प्रसार के सही समय के बारे में 43 प्रतिशत किसानों का मानना है कि ये सूचनाएं ज्यादा सही समय पर किसानों तक पहुंचाई जाती हैं। लेकिन 36 प्रतिशत किसान इन सूचनाओं का किसानों तक पहुंचने का कम सही समय मानते हैं। 16 प्रतिशत किसान यह मानते हैं कि इन सूचनाओं का प्रसार समय बहुत ज्यादा सही होता है। वहीं एक प्रतिशत किसानों का मानना है कि ये सूचनाएं बहुत कम सही समय पर किसानों तक पहुंच पाती हैं जबकि एक प्रतिशत किसान यह मानते हैं कि इन सूचनाओं का प्रसार समय बिल्कुल सही नहीं होता।

सूचनाओं की बारम्बारता की बात करें 43 प्रतिशत किसानों का मानना है कि इन सूचनाओं की बारम्बारता ज्यादा रहती है जबकि 36 प्रतिशत किसान इसे कम मानते हैं। 16 प्रतिशत किसानों की राय में इन सूचनाओं की बारम्बारता बहुत ज्यादा रहती है। जबकि एक प्रतिशत किसान इनकी बारम्बारता को बहुत कम मानते हैं और एक प्रतिशत किसान यह मानते हैं कि ऐसी सूचनाओं की बारम्बारता बिल्कुल भी नहीं होती है।

तालिका संख्या-9
फसल के मूल्य में उतार चढ़ाव के बारे में सूचना

सूचना की विश्वसनीयता	किसानों की संख्या व प्रतिशत	सूचना का सही समय	किसानों की संख्या व प्रतिशत	सूचना की बारम्बारता	किसानों की संख्या व प्रतिशत
बहुत ज्यादा	0 (0)	बहुत ज्यादा	0 (0)	बहुत ज्यादा	0 (0)
ज्यादा	0 (0)	ज्यादा	5 (1)	ज्यादा	5 (1)
कम	30 (6)	कम	45 (9)	कम	83 (16.6)
बहुत कम	243 (48.6)	बहुत कम	185 (37)	बहुत कम	193 (38.6)
बिल्कुल नहीं	227 (45.4)	बिल्कुल नहीं	265 (53)	बिल्कुल नहीं	219 (43.8)

फसल के मूल्य में समय-समय पर उतार चढ़ाव होते रहते हैं जिनकी सूचना अगर सही समय पर किसानों को मिल जाये तो वे आर्थिक फायदा इनसे उठा सकते हैं। फसल के मूल्य में उतार चढ़ाव से बारे में सरकार द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं की विश्वसनीयता के बारे में किसानों की राय सकारात्मक नहीं है। 48 प्रतिशत किसानों की राय में ये सूचनाएं बहुत कम विश्वसनीय होती हैं, जबकि 45 प्रतिशत किसान इन सूचनाओं को बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं मानते हैं। 6 प्रतिशत किसान इन सूचनाओं को कम मानते हैं।

इसी प्रकार सूचनाओं के प्रसार समय के बारे में आंकड़ों से स्पष्ट है कि 53 प्रतिशत किसान यह कहते हैं कि फसल मूल्य के उतार चढ़ाव के बारे में दी जाने वाली सूचनाओं का प्रसार समय बिल्कुल गलत होता है, जबकि 37 प्रतिशत किसान इन सूचनाओं के प्रसार के समय को बहुत कम सही मानते हैं। 9 प्रतिशत किसान इन सूचनाओं के प्रसार के समय को कम सही मानते हैं। सिर्फ एक प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो इन सूचनाओं के प्रसार समय को ज्यादा सही मानते हैं।

बारम्बारता के बारे में किसानों में से 44 प्रतिशत का मानना यह है कि फसल मूल्य से जुड़ी सूचनाओं की बारम्बारता बिल्कुल भी नहीं रहती है। जबकि 38 प्रतिशत किसान यह मानते हैं इन सूचनाओं की बारम्बारता बहुत कम होती है। 15 प्रतिशत किसानों के अनुसार इन सूचनाओं की बारम्बारता कम होती है। जबकि सिर्फ एक प्रतिशत किसान इन सूचनाओं की बारम्बारता को ज्यादा मानते हैं।

तालिका संख्या-10
सरकारी मंडी में फसल को बेचने की कदम दर कदम सूचना

सूचना की विश्वसनीयता	किसानों की संख्या व प्रतिशत	सूचना का सही समय	किसानों की संख्या व प्रतिशत	सूचना की बारम्बारता	किसानों की संख्या व प्रतिशत
बहुत ज्यादा	0 (0)	बहुत ज्यादा	0 (0)	बहुत ज्यादा	0 (0)
ज्यादा	0 (0)	ज्यादा	0 (0)	ज्यादा	0 (0)
कम	131 (26.2)	कम	175 (35)	कम	189 (37.8)
बहुत कम	231 (46.2)	बहुत कम	235 (47)	बहुत कम	229 (45.8)
बिल्कुल नहीं	138 (27.6)	बिल्कुल नहीं	90 (18)	बिल्कुल नहीं	82 (16.4)

किसी भी फसल को सरकारी मंडी में बेचने के लिये कई स्तर पर सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे फसल ढूँढ़ाई, बोली और भूगतान से जुड़ी सूचनाएं। इन सूचनाओं की किसानों फसल बेचने के दौरान आवश्यकता रहती है। सरकार द्वारा इस विषय में दी जाने वाली सूचनाओं की विश्वसनीयता के बारे में किसानों में से 46 प्रतिशत किसान इन सूचनाओं को बहुत कम विश्वसनीय मानते हैं जबकि 28 प्रतिशत किसान इन सूचनाओं को बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं मानते हैं। जबकि 26 प्रतिशत किसान इन सूचनाओं को बहुत कम विश्वसनीय मानते हैं।

फसल को बेचने से जुड़ी सूचनाओं के प्रसारण के बारे में 47 प्रतिशत किसान कहते हैं कि इन सूचनाओं का बहुत कम सही होता है। जबकि 35 प्रतिशत किसान यह मानते हैं कि इस प्रकार की सूचनाएं कम सही समय पर किसानों तक पहुंच पाती हैं। इसके अलावा 18 प्रतिशत किसान यह मानते हैं कि फसल बेचने से जुड़ी सूचनाओं का प्रसारण समय बिल्कुल गलत होता है।

बारम्बारता के बारे में आंकड़ों से स्पष्ट है कि 46 प्रतिशत किसानों का मत है कि इन सूचनाओं की बारम्बारता बहुत कम रहती है। 38 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि फसल बेचने से जुड़ी सूचनाओं की बारम्बारता कम होती है वहीं 16 प्रतिशत किसान यह मानते हैं कि इन सूचनाओं की बारम्बारता बिल्कुल भी नहीं होती है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोधपत्र के आंकड़ों से मुख्य रूप से जो तथ्य सामने आये हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध करवाई जाने वाली ज्यादातर सूचनाओं की विश्वसनीयता को लेकर किसान संशय की स्थिति में रहते हैं। बाजार में आये नये बीजों, खाद व कीटनाशकों की बात हो या नई कृषि पद्धतियों, फसल देखरेख, अनुदान, फसल मूल्य में उतार-चढ़ाव या फसल बेचने से सम्बन्धित सूचनाओं की बात हो, ज्यादातर किसान सरकार द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं पर विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि फसल श्रृण से जुड़ी सूचनाओं, फसल के लिये दी जाने वाली सब्जी और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के बारे में सूचनाओं पर किसान किसान विश्वास करते हैं लेकिन उनके अलावा अन्य प्रकार की सरकारी सूचनाओं को ज्यादातर किसान विश्वासनीय नहीं मानते हैं।

इसी प्रकार सूचनाओं का किसानों तक सही समय पर पहुंचना ज्यादा जरूरी है ताकि किसान उनका समय रहते लाभ उठा सकें। लेकिन शोध पत्र में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि सरकार कृषि से जुड़ी सूचनाओं को किसानों तक सही समय पर नहीं पहुंचा पाती। ज्यादातर कृषि सूचनाएं किसानों को सही समय पर नहीं मिल पाती हैं, कुछ किसान तो ऐसे हैं जिनका मानना है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं उन तक पहुंच ही नहीं पाती।

सूचना का प्रयोग और उसका प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि सूचनाओं का प्रसार कितनी बार लक्षित वर्ग तक किया जाता है। इस पहलु पर भी किसानों की राय ज्यादा सकारात्मक नहीं है। किसानों में से ज्यादातर का यह मानना है कि बाजार में आये नये बीज, खाद, कीटनाशक, नई कृषि पद्धतियां, फसल मूल्य में उतार-चढ़ाव और फसल बेचने से सम्बन्धित दी जाने वाली सरकारी सूचनाओं की बारम्बारता ज्यादा नहीं रहती है। हालांकि फसल श्रृण, फसल समर्थन मूल्य और अनुदान से सम्बन्धित सूचनाओं के बारे में किसानों का मानना है कि इन सूचनाओं की बारम्बारता ज्यादा रहती है।

अतः इस शोधपत्र के आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं की विश्वसनीयता को बढ़ाने की आवश्यकता है। जिसके लिये सरकार को विभिन्न संचार माध्यमों का सही प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा सूचना को किसानों तक तुरन्त और सही समय पर पहुंचाने के लिए भी सरकार को अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए ताकि किसान सरकार द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं का समय रहते लाभ उठा सकें। किसानों ने शोध के दौरान यह स्वीकार किया है कि सरकार सूचनाओं की आवृत्ति ज्यादा नहीं रखती है जिस वजह से किसान उन सूचनाओं का सही प्रयोग नहीं

कर पाते हैं अतः सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सूचना की बारम्बारता को बढ़ाया जाना जरूरी है।

संदर्भ सूची

- Annamalai Kuttayan and Sachin Rao, (2003), "What works: ITC's E-choupal and profitable rural transformation", The micro enterprise development division of the united states agency for international development (USAID), through the seep network's practitioner learning program, www.bdsknowledge.org/dyn/bds/.../ITC%20e-choupal%20India.pdf
- Banker Rajiv D. and Sabyasachi Mitra, "Impact of information technology on Agricultural commodity auctions in India", Twenty-sixth international conference on information system, 2005 http://astro.temple.edu/~banker/Conferences/Impact_of_IT_on_Agriculture.pdf
- Chandrasekhar C. P. (2003), "The Diffusion of Information Technology: The Indian Experience", Social Scientist, Vol. 31, No. 7/8 (Jul. - Aug., 2003), pp. 42-85 Published by: Social Scientist Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3518307> Accessed: 03/08/2010 02:49
- Matani Dr. A.G., "Information Technology Improving Retail Marketing In Agriculture", International Marketing Conference on Marketing & Society, 8-10 April, 2007, IIMK <http://dspace.iimk.ac.in/bitstream/2259/372/1/185-186.pdf>
- Mittal S.C., "Information Technology in Agriculture and its opportunities in India", General Manager, Management Services Division, Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited, 34, Nehru Place, New Delhi, 110019 [http://www.iffco.nic.in/applications/brihaspat.nsf/c75c8a47921f71b0e525656900233970/0238215a7f658fd765256a6100332018/\\$FILE/scm_pantnagar.pdf](http://www.iffco.nic.in/applications/brihaspat.nsf/c75c8a47921f71b0e525656900233970/0238215a7f658fd765256a6100332018/$FILE/scm_pantnagar.pdf)
- Phougat Dr. Sunil, Research Fellow, Department of Economics, "Role of Information Technology in Agriculture", M.D. University, Rohtak - 124001 (Haryana). http://www.techno-preneur.net/information-desk/science/tech-magazine/2006/aug06/Role_Agri.pdf
- Rogers E.M. and Arvind Singhal, "India's Communication Revolution", Sage Publication, New Delhi
- Roy Manas, "Aspects of rural communication", serial publication, New Delhi.
- Singh Nirvikar (2004), "Information technology and rural development in India", University of California, Santa Cruz, USA, <http://www.idfresearch.org/pdf/singh.pdf>
- Sood Aditya Dev (2001), "How to Wire Rural India: Problems and Possibilities of Digital Development", Economic and Political Weekly, Vol. 36, No. 43 (Oct. 27 - Nov. 2, 2001), pp. 4134-4141 Published by: Economic and Political Weekly Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4411303> Accessed: 03/08/2010 02:37
- Tenhunen Sirpa, University of Helsinki (2005), "Mobile technology in the village: ICTs, culture, and social logistics in India", Loyola, J. 2005. Inter-city marketing network for women micro-entrepreneurs using mobile phone: social capital brings economic development. i4d: Information for Development, July (available on-line: http://www.i4donline.net/feb05/intercity_full.asp, accessed

7 May 2008).

अश्विनी शर्मा, अब एसएमएस से सीखें खेती के गुर, दैनिक जागरण, 29

दिसम्बर, 2010, पृ.सं.-01

दिनेश श्रीवास्तव, गांव-गांव को जोड़ती सूचना तकनीक, कुरुक्षेत्र, अप्रैल 2009,

पृ.सं.-12

डॉ. अनिता मोदी, गांवों को ज्ञान क्रांति से जोड़ने की कोशिश, कुरुक्षेत्र, अप्रैल

2009, पृ.सं.-17

जतिन कुमार, संघार क्रांति ने खोले गांवों में रोजगार के द्वार,

कुरुक्षेत्र-जनवरी 2011, पृ.सं.-10

जीवन कुमार सारस्वत व पुनीत शर्मा, सूचना तकनीक से बदलती गांवों की

दुनिया, कुरुक्षेत्र, अप्रैल 2009, पृ.सं.-31

मनीष कुमार, ग्रामीण विकास के लिये जनजागरण जरूरी, कुरुक्षेत्र, जनवरी

2009, पृ.सं.-11

'मोबाईल से गरीबी भी होती है दूर', 16 अक्टूबर 2010, दैनिक जागरण पृष्ठ सं.-9

नितेश कुमार श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत और सूचना प्रौद्योगिकी, कुरुक्षेत्र, अप्रैल

2009, पृ.सं.-3

राजीव कुमार, ग्रामीण विकास के लिए चाहिए नया दृष्टिकोण, कुरुक्षेत्र, जनवरी

2009, पृ.सं.-14

Publish Research Article International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished research paper.Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review of publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- * International Scientific Journal Consortium Scientific
- * OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net